

पटना, मंगलवार, 31 दिसंबर 2019 (पौष शुक्ल पक्ष 5 संवत् 2076) ■ पटना । मुजफ्फरपुर । भागलपुर । गया । राँची । जमशेदपुर । घनकद । देवघर । कोलकाता ।



प्रभात

रेरा कर रहा बड़ी कार्रवाई. जनवरी से प्रतिदिन ₹1000 जुर्माना

70% अपार्टमेंट निर्माताओं ने रेरा को नहीं दिया हिसाब

प्रभात खबर
खास

अनिकेत त्रिवेदी > पटना

राज्य में रिक्ल इस्टेट से जुड़ी निर्माण एजेंसियों पर रेरग बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है. वर्क के अंत तक प्लन निर्माण कंपनियों ने अपने खर्च व निर्माण प्रगति का लेखा-जोखा नहीं दिया है, उन पर जनवरी महीने से प्रतिदिन एक हजार रुपये की दर से जुर्माना लगाया जाएगा. रेरा के अधिकारियों के अनुसार राज्य में करीब 860 प्रोजेक्टों का रजिस्ट्रेशन किया गया है. इनमें 100 से अधिक प्रोजेक्ट चल रहे हैं. अधिकतर का तम रक्का हुआ है. उन सभी को अपने काम को प्रगति रिपोर्ट देनी है. गान्धारी के अनुसार सिर्फ 30% करीब 250) निर्माण कंपनियों ने अब तक अपनी रिपोर्ट जमा की है. बाकी की गतिविधियों की जानकारी या को नहीं है, जबकि प्रायश्चर्न के तद्विक उन्हें प्रतिवर्ष आनी आर्थिक गतिविधियों की जानकारी देनी है.

रीरा से महावम से तेराट रिपोर्ट करनी है जमा : रेरा ने यति 31 अक्टूबर को नॉटिस जारी कर सभी रिक्ल इस्टेट कंपनियों से वार्षिक रिपोर्ट तलब की थी. रेरा की ओर • बाकी पेज 15 पर

860 प्रोजेक्टों का रजिस्ट्रेशन हुआ है राज्य में | **100** से अधिक प्रोजेक्ट अभी चल रहे | **250** निर्माण कंपनियों ने ही अब तक दी है रिपोर्ट



जनवरी से प्रोजेक्ट पर निगरानी के लिए सीए फर्म

राज्य में निर्माण होने वाले बड़े प्रोजेक्ट अपार्टमेंट, टाउनशिप की अलग-अलग जांच के लिए रेरा की ओर से सीए फर्म को रक्का जाएगा. जनवरी से निरिदा जारी कर रेरा सीए कंपनियों को अपनी रूची में शामिल करेगा. सीए फर्म बड़े निर्माण में रजट से लेकर पलेट धरिरे के अनुभव और उस सभी पहलुओं की जांच करेगा. फिर इनकी रिपोर्ट के अनुसार रेरा आगे की कार्रवाई करेगा. तद्विक इसकी निगरानी कर आम लोगों को बिल्डिंग की धोखाधड़ी से बचाव जा सके.